1989 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में यह कहा गया था कि जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा की जा रही है तथा रोजगार गारन्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की पुनः संरचना करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने वर्ष 1990-91 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा देश के चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी की गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

इंदौर-दाहोद रेलवे-लाइन का पूरा किया जाना

2292. **श्री अजीत जोगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन का कार्य कब आरम्भ किये जाने तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) इस कार्य हेतु वर्षवार क्या भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य रखे गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) और (ख) गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मकसी नयी बड़ी लाइन संपर्क का निर्माण अनुमोदित किया गया था और इसे 297.14 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत पर 1989-90 के बजट में शामिल किया गया था। 1989-90 में एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी और 1990-91 के बजट में इस कार्य के लिए 5.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। तथापि, इसकी वास्तविक प्रगति तथा पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ियों तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का विकास

2293. **श्री अजीत जोगी**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोंपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में इन योजनाओं से ऐसी बस्तियों में रहने वाले किन-किन शहरों के कितने लोगों को लाभ होगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) मलिनबस्ती निवासियों के जीवनस्तर में सुधार करने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत पेय जल पूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, पथ-प्रकाश, विद्यमान गलियों व रास्तों पर खंडजें बिछाना और सामुदायिक स्नानाघर और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया की जाती हैं। इस योजना के लिए निधियां राज्य वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध की जाती हैं और राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाएं प्रतिपादित और कार्यान्वित करती हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी मूलभूत सेवा योजना 1986-87 में आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत निवारक स्वास्थ्य सेवा और पोषण शिक्षा, स्कूल-पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और जीविका सुविधायें एवं पेय जल और पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे क्रियाकलाप सामुदायिक सहायता से किए जाते हैं।

(ग) 1981 में मध्य प्रदेश में मलिनबस्तीवासियों की अभिज्ञात जनसंख्या 10.75 लाख थी। शहरी मलिनबस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना मध्य प्रदेश सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू है। राज्य सरकार स्वयं उन कस्बों। कालोनियों को निर्धारित करती है जहां योजना आरम्भ की जाती है। 7 वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में फरवरी, 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत 7.27 लाख मलिनबस्ति निवासियों को लाभान्वित किया गया है। शहरी मूलभूत सेवा योजना मध्य प्रदेश के इन्दौर, महू, देपालपुर, सरवेर और महेश्वर में कार्यान्वित की जा रही है।